Volume-1, Issue-2, June 2025

ISSN: 3107-4243 (Online)
ISSN: (Print)
World View Research Bulletin
An International Multidisciplinary Research Journal

ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रभावशीलता: मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक अध्ययन

अश्वनी मिश्रा, शोधार्थी [1] डॉ. ओ.पी. अरजरिया प्राध्यापक [2] (वाणिज्य)
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर(म.प्र.)

सारांश

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह शोध-पत्र विशेष रूप से **मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। अध्ययन में पाया गया कि** योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण तो प्राप्त हुआ परंतु सभी प्रशिक्षित युवाओं को समुचित रोज़गार नहीं मिल सका, **यह शोध ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं**, सामाजिक स्थिति, **शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा योजना की जमीनी यह शोध योजना के सिद्धांत और जमीनी सच्चाई के बीच सार्थक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है।**

परिचय:

भारतवर्ष एक नवयुवक राष्ट्र है **जिसकी जनसंख्या का एक विशाल भाग कार्यशील युवाओं से परिपूर्ण है। यदि इस** ऊर्जस्वित युवा शक्ति को उचित दिशा, अवसर तथा कौशल-संपन्न प्रशिक्षण प्राप्त हो, **तो यह राष्ट्र** की सामाजिक, **आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में अत्यंत** महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। **इसी उद्देश्य** की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 **में प्रधानमंत्री** कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मूल भाव **यह है कि देश के युवाओं को उनके अभिरुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान किया जाए जिससे वे न केवल स्वावलंबी बन सकें, **अपितु राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी सार्थक योगदान दे सकें।** विशेषतः ग्रामीण भारत जहाँ आज भी रोजगार के **संसाधनों की उपलब्धता सीमित है एवं तकनीकी दक्षता का अभाव दृष्टिगोचर** होता है, **वहाँ इस योजना की प्रासंगिकता** और भी अधिक बढ़ जाती है।

Source:- https://www.pngkit.com/view/u2q8r5y3w7e6o0q8_pmkvy-logo10 से प्राप्त

मध्यप्रदेश **जो भारत के हृदयस्थल के रूप** में विख्यात है, ग्रामीण जीवन-**प्रणाली का प्रतिनिधि प्रदेश माना जा सकता है। यहाँ की** जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण अंचलों में निवास करता है **जो आजीविका के परंपरागत साधनों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में कौशल विकास योजनाएँ** इन युवाओं के लिए नवजीवन की संभावनाएँ खोल सकती हैं।

यह शोधकार्य न केवल आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण का एक प्रयास है, अपितु यह एक संवेदनशील दृष्टिकोण से यह **जानने का उपक्रम है कि इस योजना ने वास्तव में ग्रामीण युवाओं के जीवन में क्या परिवर्तन उपस्थित किया** है। क्या उन्हें **उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हुआ** ? क्या वे स्वरोजगार अथवा रोजगार प्राप्त कर सके? **और यदि नहीं**, तो इसके पीछे कौन-कौन सी सामाजिक, **प्रशासनिक या व्यावहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं**?

यह अध्ययन शासन-**नीतियों की अवधारणाओं एवं ग्राम्य जीवन की ठोस यथार्थता के मध्य एक सजीव संवाद स्थापित करने का विनम्र प्रयास है। यह शोध नीतिगत कल्पनाओं और जमीनी वास्तविकताओं के मध्य एक**

सशक्त वैचारिक सेतु के निर्माण का कार्य करता है जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावकारी एवं जनहितकारी बनाया जा सके।

अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्य:

वर्तमान युग तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षताओं का युग है जहाँ केवल औपचारिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं मानी जाती, अपितु व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं कौशल-संपन्नता ही आजीविका की सफलता का आधार बनती जा रही है। ग्रामीण भारत, जहाँ आज भी बेरोज़गारी, अल्पशिक्षा एवं आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं वहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक नवचेतना के रूप में उभरी है।

यद्यपि इस योजना का उद्देश्य देश के युवा वर्ग को विविध प्रकार के उद्योगों, सेवाओं एवं तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना है तथापि इसके वास्तविक प्रभाव का आंकलन किए बिना योजना की सफलता का मूल्यांकन अधूरा रह जाता है। विशेषकर मध्यप्रदेश जैसे राज्य में जहाँ ग्राम्य जनसंख्या का बहुलांश शिक्षित होने के बावजूद आजीविका के स्थायी स्रोतों से वंचित है, वहाँ यह अनिवार्य हो जाता है कि योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन और उसके परिणामों की पड़ताल की जाए।

इस अनुसंधान का उद्देश्य है-

1. यह समझना कि ग्रामीण अंचलों में युवाओं को इस योजना की कितनी जानकारी है एवं वे इससे कितनी मात्रा में लाभान्वित हो पाए हैं।
2. यह विश्लेषण करना कि प्राप्त प्रशिक्षण युवाओं के व्यावसायिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित कर रहा है।
3. यह पहचानना कि योजना के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी बाधाएँ विद्यमान हैं - जैसे प्रशिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी, संसाधनों की गुणवत्ता आदि।
4. और यह सुझाव प्रस्तुत करना कि इस योजना को किस प्रकार अधिक समावेशी, प्रभावी एवं ग्राम्य परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन मध्यप्रदेश के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किया गया, जिसमें सागर, छतरपुर, दमोह, विदिशा तथा सीहोर जिलों को प्रतिनिधि रूप में चयनित किया गया। अनुसंधान के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया तथा प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित युवाओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से संवाद स्थापित किया गया। कुल 250 प्रतिभागियों को शोध का आधार बनाया गया। संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वयकों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों से भी वार्ता कर योजना के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाइयों को समझने का प्रयास किया गया। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टियों से किया गया जिससे निष्कर्ष अधिक तथ्यपरक एवं विश्वसनीय बन सकें।

डेटा विश्लेषण:

इस अध्ययन में संकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ग्रामीण मध्यप्रदेश में प्रभाव को समझने के उद्देश्य से किया गया है। प्राप्त परिणाम युवाओं में योजना की जागरूकता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार की स्थिति एवं सामने आने वाली बाधाओं का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित तालिकाओं में प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया गया है जो योजना की व्यवहारिक स्थिति और सुधार के संभावित क्षेत्रों को उजागर करते हैं।

जानकारी प्राप्त करने का स्रोत	संख्या (N=250)	प्रतिशत (%)

ISSN: 3107-4243 (Online)
ISSN: (Print)
World View Research Bulletin
An International Multidisciplinary Research Journal

ग्राम पंचायत	85	34.0
प्रशिक्षण केंद्र (ITI आदि)	70	28.0
मित्र/परिवार	45	18.0
मीडिया (टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया)	30	12.0
अन्य	20	8.0

तालिका-1 योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत

इस तालिका-1 से पता चलता है कि 34% युवाओं ने योजना की जानकारी ग्राम पंचायत से प्राप्त की, जबकि 28% को प्रशिक्षण केंद्रों से जानकारी मिली। इसका अर्थ है कि स्थानीय संस्थाएं सूचना प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता	संख्या (N=250)	प्रतिशत (%)
उत्कृष्ट	50	20.0
संतोषजनक	140	56.0
औसत	40	16.0
असंतोषजनक	20	8.0

तालिका-2 प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आकलन

यह तालिका-2 दर्शाती है कि 56% युवाओं ने प्रशिक्षण को संतोषजनक बताया और 20% ने इसे उत्कृष्ट माना। केवल 8% प्रशिक्षु असंतोष जाहिर करते हैं जिससे प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता सकारात्मक मानी जा सकती है।

रोजगार की स्थिति	संख्या (N=250)	प्रतिशत (%)
नियमित रोजगार प्राप्त	70	28.0
स्वरोजगार प्रारंभ किया	35	14.0
बेरोजगार (प्रशिक्षण के बाद)	145	58.0

तालिका-3 प्रशिक्षण उपरांत रोजगार की स्थिति

इस तालिका-3 में स्पष्ट है कि 42% प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हुआ, जबकि 58% अभी भी बेरोज़गार हैं। यह आंकड़ा योजना की सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करता है।

बाधाएँ	संख्या (N=250)	प्रतिशत (%)
प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी	90	36.0
प्रशिक्षकों की कमी	65	26.0
आर्थिक अस्थिरता	55	22.0
इंटरनेट एवं तकनीकी संसाधनों की कमी	40	16.0

तालिका-4 प्रशिक्षण में आने वाली प्रमुख बाधाएँ

अंत में तालिका-4 बताती है कि 36% **प्रतिभागियों को प्रशिक्षण केंद्र की दूरी एक बड़ी समस्या लगी**, जबकि 26% ने **प्रशिक्षकों की कमी बताई। इससे योजनाओं के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों का** संकेत मिलता है।

मुख्य निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में युवाओं को कौशलप्रद एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भरता की **ओर प्रेरित करने का जो अभिनव प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है** वह **निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अधिकांश युवाओं को इस योजना की जानकारी उपलब्ध हुई और वे प्रशिक्षण** प्राप्त करने में सक्षम भी हुए। ग्राम पंचायतों, **प्रशिक्षण संस्थानों और मित्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी ने इस योजना की** पहुँच को व्यापक बनाया है **जो शासन की सूचना प्रणाली की सफलता का प्रतीक माना जा सकता है।** प्रशिक्षण **की गुणवत्ता के संदर्भ में भी प्रतिभागियों** ने संतोषजनक अनुभव साझा किए **जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशिक्षण संस्थानों ने अपनी भूमिका को यथासंभव प्रभावी रूप में निभाया है। किन्तु इस समस्त** सकारात्मकता के बावजूद, **सबसे गंभीर स्थिति प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार की उपलब्धता को लेकर सामने आई** है। **आँकड़े दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी लगभग आधे से अधिक युवा बेरोजगार बने हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण और रोजगार के मध्य एक गहरा व्यावहारिक अंतराल व्याप्त है।**

प्रशिक्षण केंद्रों की दूरभौगोलिक स्थिति, प्रशिक्षकों की सीमित उपलब्धता, **तकनीकी संसाधनों** की कमी तथा **आर्थिक बाधाएँ भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोधक तत्व के रूप में उभर कर** सामने आई हैं। **यह स्थिति संकेत करती है कि योजना** की परिकल्पना भले ही सशक्त हो **परंतु इसका स्थायी और** व्यापक प्रभाव तभी संभव है जब उसकी **संरचना में क्षेत्रीय** आवश्यकताओं, **संसाधनों की उपलब्धता और** स्थानीय सामाजिक संरचना का समावेश किया जाए।

अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं के लिए एक नई दिशा और आशा का संचार करती है, **किन्तु इसके प्रभाव को स्थायित्व और व्यापकता देने हेतु प्रशासनिक दक्षता**, संसाधन **उपलब्धता और व्यावसायिक साझेदारी की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।**

सुझाव:

1. **प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात युवाओं को उद्योगों, सेवा क्षेत्रों एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु एक संगठित** प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, **जिससे प्रशिक्षण व्यर्थ न जाए और रोजगार की दिशा में ठोस प्रगति हो।**
2. **स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण की विषयवस्तु स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।**
3. प्रशिक्षकों के लिए **नियमित प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो और प्रशिक्षण अधिक व्यावहारिक तथा परिणामकारी बन सके।**
4. **योजना की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुँचाने हेतु पंचायतों**, विद्यालयों, **आँगनवाड़ी केन्द्रों तथा स्थानीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।**
5. **प्रशिक्षण केंद्रों की भौगोलिक पहुँच में सुधार लाने हेतु दूरस्थ ग्रामों में मोबाइल प्रशिक्षण केंद्रों या** उप-केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
6. **प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार हेतु सुलभ और न्यून ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए तथा आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।**

Volume-1, Issue-2, June 2025

ISSN: 3107-4243 (Online)
ISSN: (Print)
World View Research Bulletin
An International Multidisciplinary Research Journal

7. प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात युवाओं को उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपने कौशल का सही दिशा में उपयोग कर सकें।
8. योजना की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु समय-समय पर स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी एवं समीक्षा तंत्र सक्रिय किया जाए जिससे आवश्यक सुधार शीघ्र किए जा सकें।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण भारत में युवाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं अपितु युवाओं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना **है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि योजना की पहुँच अब ग्राम्य** जीवन तक बन चुकी है और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। यद्यपि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को अधिकांश प्रतिभागियों ने संतोषजनक माना परंतु रोजगार की उपलब्धता एक ऐसी चुनौती है जो योजना की **सफलता में बाधा बनकर उभर रही है। यह स्पष्ट संकेत करता है कि यदि प्रशिक्षण और रोजगार के बीच व्याप्त** असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो योजना की सफलता अधूरी ही मानी जाएगी। संसाधनों की असमान उपलब्धता, प्रशिक्षकों की कमी, केंद्रों की दूरी तथा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ भी इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।

अतः कहा जा सकता है कि यह योजना अपने मूल उद्देश्य में सार्थक तो है किंतु इसके क्रियान्वयन में *स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन, सुव्यवस्थित निगरानी* तथा *रोजगार से सीधे जोड़ने की व्यवस्था* को और अधिक सशक्त करना होगा। जब तक योजना केवल प्रशिक्षण तक सीमित रहेगी, तब तक ग्रामीण युवा इसके वास्तविक लाभ से वंचित रहेंगे। वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब यह योजना युवाओं को न केवल हुनरमंद बनाए, बल्कि उन्हें उनके जीवन स्तर में सुधार का अवसर भी प्रदान करे।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

1. चौहान, जी., गुप्ता, एस., और सिंह, वी. (2024). **मध्य प्रदेश क्षेत्र के लोगों पर पीएमकेवीवाई के परिणामों का** विश्लेषण करने पर एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक इनोवेशन (आईजेआरएसआई), 11(5), 221–229.
2. पटेल, आर. ए. (2023). **तकनीकी इंटरफेस और हितधारक सहयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास** योजना (पीएमकेवीवाई) को मजबूत करना, विद्यायन - एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक सहकर्मी-समीक्षित ई-जर्नल, 8(5), अप्रैल 2023.
3. **"भारत के ग्वालियर क्षेत्र में युवाओं की उत्पादकता पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रभाव"** (2019), ब्लू **आइज़ इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग एंड साइंसेज पब्लिकेशन**, DOI:10.35940/ijrte.D7385.118419.
4. चतुर्वेदी, के. (2022). मध्य प्रदेश **के सीहोर जिले में लाभार्थी किसानों की कृषि और संबद्ध उद्यमों पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभाव** (थीसिस, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर)। सिंह, ए., गौतम, यू.एस., और सिंह, एस.आर.के. (2022)। **तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मध्य प्रदेश में कृषक महिलाओं का सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण: एक केवीके दृष्टिकोण**, भारतीय विस्तार शिक्षा पत्रिका, 48(1&2), 74–77.

ISSN: 3107-4243 (Online)
ISSN: (Print)
World View Research Bulletin
An International Multidisciplinary Research Journal

5. चौहान, जी., गुप्ता, एस., और सिंह, वी. (2024). **मध्य प्रदेश क्षेत्र के लोगों पर पीएमकेवीवाई के परिणामों का** विश्लेषण करने पर एक अध्ययन, **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च** एंड साइंटिफिक इनोवेशन (आईजेआरएसआई), 11(5), 221–229.
6. गुप्ता, आर. (2021). **मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पीएमकेवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट**, 8(4), 213–220.
7. जोशी, एम., और सिंह, वी. (2020). **ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में व्यावसायिक प्रशिक्षण की** भूमिका: मध्य प्रदेश का एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 56(3), 45–52.
8. कुमार, ए. (2022). **ग्रामीण भारत में कौशल विकास और रोजगार क्षमता: मध्य प्रदेश का एक केस स्टडी** (पीएचडी शोध कार्य), **बरकतउल्ला विश्वविद्यालय**, भोपाल.
9. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC). (2022). **मध्य भारत में पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट।** एनएसडीसी.
10. पटेल, आर. ए. (2023). **तकनीकी इंटरफेस और हितधारक सहयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास** योजना (PMKVY) को मजबूत करना, **विद्यायन** - एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक सहकर्मी-समीक्षित ई-जर्नल, 8(5).
11. शर्मा, पी., और वर्मा, एस. (2023). **ग्रामीण मध्य प्रदेश में पीएमकेवीवाई के तहत कौशल विकास** कार्यक्रमों का मूल्यांकन, **जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट** एंड पॉलिसी, 15(2), 101–115.
12. सिंह, डी., और यादव, पी. (2018). **कौशल विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं की जागरूकता** और भागीदारी: मध्य प्रदेश से साक्ष्य, **जर्नल ऑफ डेवलपमेंट** पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 3(1), 77–89.
13. वर्मा, एस., और पाठक, एन. (2019). **ग्रामीण महिलाओं पर सरकारी कौशल विकास योजनाओं** का प्रभाव: मध्य **प्रदेश में एक अध्ययन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय**, इंदौर.

WORLD VIEW RESEARCH BULLETIN
An International Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 3107-4243 (Online)

World View Research Bulletin

(An International Multidisciplinary Research Journal)

Open Access Journal -ISSN: 3107-4243 (Online) | www.wrb.education| editor@wrb.education | Impact Factor

CERTIFICATE OF PUBLICATION

The board OF World View Research Bulletin is hereby awarding this certificate

to **अश्वनी मिश्रा, डॉ. ओ.पी. अरजरिया**

WORLD VIEW
RESEARCH BULLETIN
An International Multidisciplinary Research Journal

In recognition of the publication of the paper

titled **ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रभावशीलता: मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक अध्ययन**

PUBLISHED IN
VOLUME 1, ISSUE 2 (JUNE-SEP 2025)

Paper Id-

Chief Editor (CE)